दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/962 15/01/2025

प्रति,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

<u>विषय: "क्या MABS के आयात पर शून्य शुल्क की सिफारिश की जा सकती है" पर सदस्यों के सुझाव।</u>

हमें भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के FT (ASEAN) प्रभाग से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में एक व्यापारी द्वारा MABS उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के अनुरोध पर Plexconcil सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं। व्यापारी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है:

- MABS ऑटोमोटिव, घरेलू उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं और खिलौनों जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक प्रमुख आयातित प्लास्टिक कच्चे माल में से एक है। यह अंतिम तैयार उत्पाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वितरक उपरोक्त उद्योगों के लिए तैयार उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यक कच्चे माल में से एक के रूप में MABS का आयात करता है
- भारत के वितरक ने बताया कि मलेशिया दुनिया भर में सबसे बड़े MABS उत्पादक देशों में से एक है। मलेशियाई MABS ने पहले ही अपनी विशेषज्ञता और क्षमताओं को एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसे दुनिया भर के प्रतिष्ठित ग्राहकों द्वारा स्वीकार और सराहा गया है।
- भारत में एमएबीएस के लिए बाजार का आकार अपेक्षाकृत छोटा है, और इस विशिष्ट सामग्री की मांग बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादन को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि वितरक द्वारा बताया गया है।
- वितरक ने यह भी बताया कि भारत में MABS बाजार की जैविक वृद्धि वर्तमान में 5%-10% की सीमा में है, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में MABS का स्थानीय उत्पादन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है। यह देश भर के उद्योगों के लिए MABS की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति के लिए आयात को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में मान्यता देने के महत्व को रेखांकित करता है।

- यह उत्पाद भारत-आसियान एफटीए के अंतर्गत आता है और इस पर 5% (एमएफएन के तहत 7.5%) का आयात शुल्क लगता है, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालता है।
- इस शुल्क को 0% तक कम करके, हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और इन उत्पादों को जनता के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं। वितरक ने MABS उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के संभावित लाभों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम संबंधित सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर अपनी राय दें कि क्या एमएबीएस के आयात पर शून्य शुल्क की सिफारिश की जा सकती है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद